

F.No.8/3/2015-EP
Government of India
Ministry of Textiles

Udyog Bhavan, New Delhi
2nd November, 2015

To

The Manager,
Government of India Press,
Faridabad, Haryana.

Sub: Policy regarding Recovery of EMD / BG amount lying unclaimed by the readymade garment exporters under the then Garment & Knitwear Export Entitlement (Quota) Policy (2000-2004).

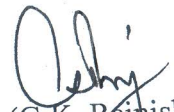
Sir,

I am directed to forward herewith copy of S.O.No.8/3/2015-EP vide which the Government has decided to substitute Para 12 (C) of Notification No. 1/128/99-Exports-I dated 12th November, 1999.

2. All other terms and conditions of the above Notification dated 12th November, 1999 shall remain unchanged.

3. The soft copy of the same is being sent by email on 3/11/15 at fd-gippr@nic.in, duly certified that the content of the soft copy as well as hard copy are same and also approved by the competent authority.

Yours faithfully,



(G.K. Rajnish)

Under Secretary Government of India

Ph. 2306 3837

Fax No.2306 1973

Email: teptj2@nic.in

Encl: As above.

Copy for information to :-

1. Textile Commissioner, Office of TXC, Mumbai.
2. Secretary General, AEPC, Gurgaon.
3. ✓ NIC, Ministry of Textiles – with a request to upload the above gazette notification in the Ministry's web-site.

To Whom so ever it may concern

This to certify that contents of the soft copy as well as hard copy of S.O. No.8/3/2015-EP dated 2nd November, 2015 in respect of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy (Hindi and English version) are same and approved by the competent authority.

Place : New Delhi

Dated. 3/11/2015.....

Signature.....

Name : G.K. Rajnish

Designation : Under Secretary

The Gazette of India

[TO BE PUBLISHED IN PART-I, SECTION OF GAZETTE OF
INDIA, EXTRAORDINARY,]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TEXTILES

S.O. No.8/3/2015-EP

New Delhi, Dated the 2nd November, 2015

NOTIFICATION

Sub: Policy regarding Recovery of EMD/BG amount lying unclaimed by the readymade garment exporters under the then Garment & Knitwear Export Entitlement (Quota) Policy (2000-2004).

Whereas operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy (2000-2004) [GKEEP] was notified initially for one year with effect from 1st January, 2005, vide Notification No.1/61/2004- Exports-I dated 9th November, 2004, and same has been extended from time to time up to 31st December, 2016.

2. Whereas the aforesaid Policy had a provision for submission of Ernest Money Deposit (EMD) / Bank Guarantee (BG) by the concerned exporters as a guarantee towards fulfilling the export obligations within the stipulated period, failing which the EMD/BG is liable to be forfeited.

3. Whereas EMDs deposited by the exporters were either released or forfeited by the designated authorities based on exporters' performance as per procedure under which the exporters were required to submit documentary proofs in support of shipment to Quota Administering Authority (QAA).

4. Whereas it has been observed from the Audited Accounts of Apparel Export Promotion Council (AEPC), that an unclaimed amount of Rs. 48.58 crores is lying with AEPC in the form of fixed deposits and demand drafts, details of which are maintained by AEPC. This amount belongs to the GoI, which AEPC was holding as the Custodian. This unclaimed amount of Rs. 48.58 cr. has been lying for more than 10 years in absence of any preferred claims as per guidelines.

5. Now therefore, in exercise of the powers conferred in the Garment & Knitwear Export Entitlement (Quota) Policy (2000-2004) extended till 31.12.2016 (para 20), in respect of countries where such exports are covered by restraints under the provisions of the Agreement of Textiles and Clothing,

h

is hereby **substituted** as under in place of Para 12 (C) of Notification No. 1/128/99-Exports-I dated the 12th November, 1999.

*“An opportunity is hereby given to the exporters covered under the Policy to submit their claims for refund, if any, along with all the supporting documents **within 90 days** from the date of this Notification before QAA, provided that all such DD/ Fixed Deposit Receipts, for which no claim is received within the stipulated period **shall stand forfeited along with interest earned** by the Quota Administering Authority in favour of Govt. of India to be deposited in the Consolidated Fund of India (CFI). No claim of any apparel exporter, whatsoever, shall be entertained in respect of the said unclaimed Demand Drafts/Fixed Deposit Receipts on any ground whatsoever after the expiry of the stipulated period of 90 days.”*

6. Accordingly exporters, who have submitted BG/EMD, in respect of the amount deposited as mentioned in para 4 above, are requested to submit their claims as indicated, failing which the said amount will stand forfeited in favour of the Government of India.


(Neerav K Mallick)
Director

Note: The original Notification was published vide No.1/128/99-Exports-I dated 12.11.1999 and last amended vide Notification No.1/61/2004-IT dated 14.10.2015.

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

एस.ओ.सं.8/3/2015-ईपी

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विषय: तत्कालीन परिधान एवं निट वियर निर्यात पात्रता (कोटा) नीति (2000-2004) के अंतर्गत सिलेसिलाए परिधान निर्यातकों द्वारा दावा नहीं की गई ईएमडी/बीजी राशि की वसूली से संबंधित नीति।

हालांकि परिधानों और निट वियर की निर्यात पात्रता (कोटा) नीति (2000-2004) (जीकेईईपी) के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन दिनांक 09 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-1 के माध्यम से 01 जनवरी, 2005 से आरंभ में 1 वर्ष के लिए अधिसूचित किया गया था और इसका कार्यकाल समय-समय पर 31 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ाया गया है।

2. जबकि उपर्युक्त नीति में संबंधित निर्यातकों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए गारंटी के रूप में बयाना (ईएमडी)/बैंक गारंटी (बीजी) को प्रस्तुत करने का प्रावधान था, ऐसा न करने पर ईएमडी/बीजी को जब्त कर लेने का प्रावधान था।

3. जबकि निर्यातकों द्वारा जमा की गई ईएमडी क्रियाविधि के अनुसार निर्यातकों के निष्पादन जिसके अंतर्गत निर्यातकों को कोटा को प्रशासित करने वाली प्राधिकरण (क्यूएए) को शिपमेंट के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित था, के आधार पर पदनामित पदाधिकारियों द्वारा या तो रिलीज कर दी गई थी अथवा जब्त कर ली गई थी।

4. जबकि अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के लेखापरीक्षित लेखाओं से यह पाया गया है कि ईपीसी के पास सावधि जमा और डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 48.58 करोड़ रुपए की दावा नहीं की गई राशि पड़ी हुई है जिसका ब्योरा ईपीसी द्वारा रखा जा रहा है। यह राशि भारत सरकार की है जिसे ईपीसी कस्टोडियन के रूप में रखे हुए था। दावा नहीं की गई 48.58 करोड़ रुपए की राशि दिशानिर्देशों के अनुसार किसी अधिमानी दावे के अभाव में 10 वर्ष से अधिक समय से पड़ी हुई है।

A. S. S.

5. इसलिए अब उन देशों के संबंध में जहां ऐसे निर्यात वस्त्र और क्लोदिंग के करार के प्रावधानों के अंतर्गत निषेधों द्वारा कवर किया जाता है, 31.12.2016 (पैरा 20) तक विस्तारित किए गए परिधान एवं निट वियर निर्यात पात्रता (कोटा) नीति (2000-2004) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे एतद्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना सं. 1/28/99-निर्यात-1 के पैरा 12 (सी) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

‘जमानत वापसी, यदि कोई हो, के लिए क्यूएए के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिन के भीतर सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने की नीति के अंतर्गत शामिल किए गए निर्यातकों को एतद्वारा दावे हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है यह भी प्रावधान है कि ऐसे सभी डीडी/सावधि जमा रसीदें, जिसके लिए निर्धारित अवधि के भीतर कोई दावा प्राप्त नहीं होगा, को भारत सरकार के पक्ष में कोटा प्रशासित करने वाले प्राधिकरण द्वारा उपार्जित ब्याज सहित जब्त करके इसे जिसे भारत के समेकित निधि (सीएफआई) में जमा कर दिया जाएगा। 90 दिन की निर्धारित अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी हालात में उक्त दावा नहीं किए डिमांड ड्राफ्ट सावधि जमा रसीदों के संबंध में किसी अपैरल निर्यातक चाहे जो कोई भी हो, के किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा’।

6. तदनुसार जिन निर्यातकों ने उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित जमा राशि के संबंध में बीजी/ईएमडी प्रस्तुत किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने दावे प्रस्तुत कर दें, ऐसा न करने पर उक्त राशि भारत सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

श्री. ए. मलिक

(नीरव के. मलिक)

निदेशक

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 12.11.1999 के सं. 1/128/99-निर्यात-1 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी और पिछली बार दिनांक 14.10.2015 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-आईटी के माध्यम से संशोधित की गई थी।